मधुमिता दास और अन्य

बनाम

उड़ीसा राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 254/2008)

11 जून 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और पी.पी. नाओलेकर, जेजे.]

न्यायपालिका

उच्चतर न्यायिक सेवा - अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती - 16 पदों के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2008 का विज्ञापन संख्या 1 - फास्ट ट्रैक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त 9 तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएँ* - अभिनिधोरित। विज्ञापन के अनुसार चयन की प्रक्रिया जारी रह सकेगी, लेकिन यह केवल 7 पदों के संबंध में होगी, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित 9 पदों के संबंध में - याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक पदों पर बने रहेंगे - यह है यह स्पष्ट किया जाता है कि जब भी नियमित रिक्तियां आएंगी, याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विधिवत विचार किया जाएगा - उन्हें जिला जज के कैडर में भर्ती के लिए होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

*बृज' मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य। **(2002 (5) एससीसी 1 - संदर्भित।**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 250/2008।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

साथ

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 254/2008।

उदय यू. ललित, रचना श्रीवास्तव याचिकाकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया-

नोटिस जारी करें।

इन रिट याचिकाओं में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2008 के विज्ञापन संख्या 1 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया है।

बृज मोहन लाल बनाम भारत का संघ और अन्य (2002 (5) एससीसी 1) में। उनकी शिकायत है कि विज्ञापित 16 पदों में दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान में रखे गए 9 पद भी शामिल हैं। यह बताया गया है कि विज्ञापन में तय पात्रता मानदंड वर्तमान याचिकाकर्ताओं को बाहर कर देता है। सबसे पहले, उनमें से कुछ की आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक है और दूसरे, न्यायिक अधिकारी होने के नाते, वे बार के सदस्यों के लिए विज्ञापित पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह भी बताया गया है कि इस न्यायालय के द्वारा बृज मोहन के मामले (सुप्रा) में पैराग्राफ -10, दिशा संख्या 4 में जो कहा गया है, उसके संदर्भ में, उन्हें (तदर्थ पदों में) जारी रखा जाना चाहिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों से संबंधित उसके बाद फास्ट ट्रैक अदालतों के कार्य बंद करने के बाद, उपलब्ध नियमित पदों के संबंध में। उनके मामलों पर विचार तभी किया जाएगा जब उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाएगा। उनका कहना है कि इन्हें समय-समय पर जारी रखा जाता रहा है। जाहिर है, उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। वर्तमान में, हम उस प्रश्न से चिंतित नहीं हैं जिसकी प्रासंगिकता केवल नियमित रिक्तियों के संबंध में उनके अवशोषण पर विचार करने के समय हो सकती है। यह श्री उदय यू. ललित द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वरिष्ठ वकील ने कहा कि प्रदर्शन का आकलन करते समय, अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं, यानी याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करते समय समान मापदंडों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि जो

भर्ती किये गये हैं एक अन्य स्त्रोत, अर्थात न्यायिक अधिकारियों में से। हमें इस दलील में भी दम नजर आता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि 2008 के विज्ञापन संख्या 1 के अनुसार चयन की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन वह केवल 7 पदों के संबंध में होगी, और वर्तमान में याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद 9 पदों के संबंध में नहीं यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने विज्ञापन जारी होने के बाद पर्याप्त संख्या में मामलों का निपटारा नहीं होने के संबंध में कुछ पत्र जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कारण बताए हैं कि मामलों का पर्याप्त निस्तारण क्यों नहीं हो सका। कहने की जरूरत नहीं है कि उच्च न्यायालय नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता का निर्णय करते समय प्रतिक्रियाओं में अपनाए गए रुख पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे, जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब भी नियमित रिक्तियां आएंगी, याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विधिवत विचार किया जाएगा। फिर जिला जज के कैडर में भर्ती के लिए होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

इन मामलों को सितंबर, 2008 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।

इस बीच, जवाबी और प्रत्युत्तर शपथ पत्र, यदि कोई हो, दाखिल किया जाऐंगे।

आर.पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेणु कुमारी गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।